डमोह पन्ना सागर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक एवं एएनआर.

बनाम

मुन्ना लाल जैन

16 दिसम्बर 2004

(अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.)

सेवा कानूनः

सेवा से निष्कासन/समाप्ति-दंड की मात्रा- उच्च न्यायालय द्वारा-हस्तक्षेप-बैंक प्रबंधक ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनधिकृत रूप से एक निश्चित राशि निकाल ली- अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उक्त बैंक प्रबंधक की सेवाएं समाप्त कर दी - अपील पर, उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया मामला और बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति के अलावा कोई सजा पारित करें-धारणा की शुद्धताः न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा को चौंकाने वाला न हो-का दायरा न्यायिक समीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक ही सीमित है, न कि निर्णय तक-उच्च न्यायालय ने कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि लगाई गई सजा किसी त्रुटि से ग्रस्त है- इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर

दिया।

प्रशासनिक व्यवस्थाः

कारणों को रिकार्ड करना-महत्व एवं आवश्यकता-समझना।

प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-बैंक के शाखा प्रबंधक के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनधिकृत रूप से निश्चित राशि निकाल ली। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दीं।

अपील पर, उच्च न्यायालय, ने अपीलीय प्राधिकारी को मामले पर पुनर्विचार करने और प्रत्यर्थी की सेवाओं को बर्खास्त करने, हटाने या समाप्त करने के अलावा कोई भी सजा देने का निर्देश दिया। इसलिए अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभीनिर्धारित: 1 न्यायालय को प्रशासक के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक कि निर्णय अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा को चौंकाने वाला न हो, इस अर्थ में कि वह तर्क या नैतिक मानकों की अवहेलना में न्यायालय का प्रशासक द्वारा चुने गए विकल्प की सत्यता जो उसके लिए खुली है में नहीं जाना चाहिए और न्यायालय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर

अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक ही सीमित है, निर्णय तक नहीं।{1043 जी-एच}

ओम कुमार बनाम भारत संघ, {2001} 2 एससीसी 386; बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, {1995} 6 एससीसी 749 और भारत संघ बनाम जी, गणयुथम, {1997} 7 एससीसी 463, पर अवलंबन लिया।

पुनः वेडनसबरी, (1948) 1 केबी 223 और काउंसिल फॉर सिविल सर्विसेज यूनियन बनाम सिविल सर्विसेज मंत्री, {1983} 1 एसी 768, का उल्लेख किया गया है।

2.1 मुकदमो को छोटा करने के लिए अदालत/न्यायाधिकरण, असाधारण और दुर्लभ मामलो में, उसके समर्थन में ठोस कारण दर्ज करके उचित सजा दे सकता है। सामान्य प्रक्रिया में यदि दी गई सज़ा आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को लगाये गए दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना उचित होगा।{1044-ए-बी}

2.2 मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने कोई कारण दर्ज नहीं किया इसने कैसे और क्यों सज़ा को आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन पाया। यहां तक कि इस पहलू पर कोई विवेचन भी नहीं है। {1044-सी}

3. एक बैक अधिकारी को ईमानदारी और अखण्डता के उच्च मानकों

का पालन करना आवश्यक है- वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के पैसे का लेनदेन करता है। बैंक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम से निभाए और ऐसा कुछ भी न करे जो एक बैंक अधिकारी के लिए अशोभनीय हो। अच्छा आचरण और अनुशासन बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कामकाज से अविभाज्य हैं। {1044-डी}

4. यह कहना कोई बचाव नहीं है कि उस मामले में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ जब अधिकारी/कर्मचारी ने अधिकार के बिना काम किया। किसी संगठन, विशेष रूप से बैंक, का अनुशसन उसके प्रत्येक अधिकारी और अधिकारी पर निर्भर करता है जो अपेन आवंटित क्षेत्र के भीतर कार्य करते है और संचालन करते है। अपने अधिकार से परे कार्य करना अपने आप में एच अनुशासन का उल्लंघन है और दुर्व्यवहार है। कर्मचारी पर आरोप साधारण प्रकृति के नहीं थे और गंभीर थे। ऐसा प्रतीत नहीं हेाता है कि इन पहलुओं को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा है। {1044-ई-एफ}

अनुशासनिक प्राधिकारी सह क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम निकुंज बिहारी पटनायक {1996} 9 एससीसी 69, अवलंबन लिया गया।

5.1 जब किसी न्यायालय को लगता है कि सज़ा आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है, तो उसे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों को दर्ज करना होगा। मात्र यह अभिव्यक्ति कि सज़ा आश्चर्यजनक रूप से असंगत है,

कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। {1044-जी}

ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन, (1971) 1 ऑल ईआर 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री, (1974) एलसीआर 120, संदर्भित।

5.2 कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते है। कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय, ''स्फिंक्स के गूढ चेहरे'' को उजागर करता है, तो यह अपनी चुप्पी से, वैधता का निर्णय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने के अपने अपीलीय कार्य को निष्पादित करना अदालतों के लिए लगभग असंभव बना सकता है। फैसले के आधार का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक दिए गए आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है। {1045-ए-बी-सी}

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़, {2003}4 एससीसी 364, अवलंबन लिया।

5.3 मौजूदा मामले में हाई कोर्ट का फैसला किंतु-परंतु से भरा है। ऐसा कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि सज़ा किसी त्रुटि से

पीड़ित है। सज़ा की मात्रा पर पुनर्विचार का निर्देश देने का कोई आधार नहीं बताया गया है। प्रतिवादी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने में बुरी तरह असफल रहा। {1045-डी}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 8258/2004 की।

मध्य प्रदेश के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.04.2004 से उच्च न्यायालय में एल.पी.ए. 2001 की संख्या 116.

अपीलकर्ताओं की ओर से प्रकाश श्रीवास्तव।

सुश्री हेमा साहू एवं सी.एल. प्रतिवादी की ओर से साहू।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.: स्वीकार की गयी

डमोह पन्ना सागर, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक- अपीलकर्ता संख्या 1 (यहां बाद में नियोक्ता के रूप में संदर्भित) जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले वैधता पर सवाल उठाता है, जिसमें नियोक्ता बैंक के निदेशक मंडल (संक्षेप में 'बोर्ड) को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। मामला और प्रतिवादी - मुन्ना लाल जैन की बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति के अलावा कोई भी सज़ा पारित करें

(इसके बाद 'कर्मचारी के रूप में संदर्भित)।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैः

इस आरोप पर कि काबरा शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी ने अनाधिकृत रूप से 25,000 रुपये की राशि निकाल ली और ऐसा कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है। गंभीर दंड, इस तरह की अनधिकृत निकासी के कारण, उनके खिलाफ दिनांक 14.10.1992 के आरोप पत्र द्वारा आरोप तय किए गए थे कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 06.05.1992 को 25,000 रुपये की राशि निकाली। प्रतिवादी-कर्मचारी ने अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया। हालांकि, राशि निकालने के तथ्य पर विवाद नहीं करते हुए, उन्होंने दलील दी कि प्रासंगिक अवधि के दौरान उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई थी और तत्काल शल्य चिकित्सा के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उन्होंने रुपये निकालने की सूचना दमोह मुख्यालय को दे दी थी। स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिसने 20.07.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कर्मचारी आरोपों का दोषी था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति जताई और औपचारिकताओं का पालन करने यानी कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद निष्कासन का आदेश पारित किया। अपील में उक्त आदेश को कायम रखा गया। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी ने रिट

याचिका संख्या 2719/1995 दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि लगाए गए आरोपों को विधिवत रूप से पेश किया गया है, लेकिन सजा की मात्रा के संबंध में मामले को पुनर्विचार के लिए अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया गया। निर्देश के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा मामले पर फिर से विचार किया गया और यह माना गया कि हटाने के आदेश के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं।

कर्मचारी ने एक रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. संख्या 4812/1998) दायर की। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि बोर्ड ने 13.05.1998 के पहले आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर सभी कोणों से विचार नहीं किया था। हटाने के दंड पर दोबारा विचार करने का निर्देश बोर्ड को दिया गया। मामले पर फिर से विचार किया गया और बोर्ड ने सज़ा की मात्रा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश को 2000 की रिट याचिका संख्या 5236 में चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि आरोप साबित हो गए थे और बोर्ड ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि पत्नी की बीमारी का तथ्य साबित नहीं हुआ है क्योंकि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मामला डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील में ले जाया गया। डिवीजन बेंच के समक्ष कर्मचारी का कहना था कि आपात्कालीन स्थिति के कारण पैसा निकाला गया था और उसके भविष्य निधि खाते में कुछ पैसे थे। किसी भी स्थिति में, पैसा 24 प्रतिशत ब्याज के साथ बैंक में जमा किया गया था, जो बिना सुरक्षा यानी ओवरड्राफ्ट के लिए ऋण पर देय से बहुत अधिक था।

जवाब में, नियोक्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सजा की मात्रा में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः उच्च न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालाँकि, यह देखा गया कि राशि 24 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाई गई है। यह देखा गया कि यद्यपि पत्नी की बीमारी को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं रखी गई थी, जो निष्कासन की सजा को बरकरार रखने का आधार नहीं हो सकती थी, खासकर जब उसने 24 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस कर दी थी। ऐसा कोई आरोप नहीं था कि पहले उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया हो। यह नोट किया गया कि पूर्ववृत्त सभी मामलें में सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें पूरी तरह से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। कैलाश नाथ गुप्ता बनाम जांच अधिकारी (आरके राय) इलाहाबाद बैंक और अन्य, एआईआर (2003)

एससी 1377 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। यह भी देखा गया कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि 46,000 रुपये की राशि पहले ही चुका दी गई है और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यद्यपि तथ्यात्मक मैट्रिक्स अलग पाया गया, फिर भी यह माना गया कि शाखा प्रबंधक ने एक कठिन परिस्थिति में पैसा निकाला था और 24 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाया था। कोई नुकसान नहीं हुआ। उच्च न्यायायल ने फिर से कहा कि उसने यह कहने में जल्दबाजी की। उनका यह मत नहीं है कि जब तक कोई हानि न हो तब तक कोई दुराचार नहीं हो सकता। अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक उपयुक्त मामला था जहां बोर्ड को कर्मचारी के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त दयालु और दयालु होना चाहिए ताकि बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति के अलावा कोई अन्य सजा दी जा सके। यह माना गया कि अनियमितता थी लेकिन ऐसी अनियमितता नहीं थी कि हटाने की सजा दी जाए। यह भी संकेत दिया गया कि कम सजा दिए जाने पर भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय विरोधाभासों से भरा है। यह स्वीकार करने के बाद भी कि सजा की मात्रा में हस्तक्षेप की व्यावहारिक रूप से कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी अप्रासंगिक विचारों पर उच्च न्यायालय ने निर्देश

दिया कि निष्कासन, समाप्ति या बर्खास्तगी की सजा पारित नहीं की जानी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में सज़ा की मात्रा में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर प्रकाश डाला गया है और यह एक ऐसा मामला है जहां किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह पाया गया कि कर्मचारी द्वारा किया गया बचाव झूठा था। हालाँकि उन्होंने दावा किया कि राशि 09.05.1992 को निकाली गई थी, वास्तव में यह 06.05.1992 को निकाली गई थी। पत्नी की बीमारी के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

जवाब में, प्रतिवादी-कर्मचारी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपील पोषणीय नहीं है और अपील वास्तव में अनावश्यक है। आमतौर पर इस न्यायालय को साक्ष्यों की विवेचना करके सेवा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रतिवादी-कर्मचारी ने प्रधान कार्यालय को रुपये निकालने के बारे में सूचित किया था जो कि वास्तविक है और उसने 24 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि चुका दी थी।

सजा कि मात्रा में हस्तक्षेप का दायरा इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का विषय रहा है। इस तरह का हस्तक्षेप कोई नियमित मामला नहीं हो सकता।

लॉर्ड ग्रीन ने 1948 में प्रसिद्ध वेडनसबरी मामले में कहा था (1948(1) केबी 223) कि जब कोई कानून किसी प्रशासक को निर्णय लेने

का विवेक देता है निर्णय के अनुसार, न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित रहेगा। उन्होंने कहा निम्नलिखित में से एक या दूसरे को छोड़कर हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी शर्तें संतुष्ट थीं, अर्थात् आदेश कानून के विपरीत था, या प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया गया, अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया गया; या निर्णय ऐसा था जो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था। इन प्रशासनिक कार्यवाही की वैधता का आकलन करने के लिए यूके और भारत में सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया। यह भी समान रूप से सर्वविदित है कि 1983 में, काउंसिल फॉर सिविल सर्विसेज यूनियन बनाम सिविल सेवा मंत्री, {1983} एसी 768 (जिसे सीसीएसयू केस कहा जाता है) में लॉर्ड डिप्लॉक ने एक या दूसरे पर आधारित प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का सारांश दिया था। निम्नलिखित में से, अवैधता, प्रक्रियात्मक अनियमितता और तर्कहीनता। हालाँकि, उनकी राय थी कि" " " "

ओम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ,{2001}2 एससीसी 386 में, यह न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गयाः

> "यह सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी में प्रशिया में उत्पन्न हुआ और तब से इसे जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में अपनाया गया है। लक्ज़मबर्ग में यूरोपीय न्यायालय और

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने प्रशासनिक की वैधता का निर्णय करते समय इस सिद्धांत को लागू किया है। लेकिन, उससे भी बहुत पहले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से विधायी कार्रवाई के लिए ''आनुपातिकता' के सिद्धांत को लागू किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

''आनुपातिकता'' से हमारा तात्पर्य इस प्रश्न से है कि क्या मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय विधायिका या प्रशासक द्वारा उपायों का उचित या न्यूनतम-प्रतिबंधात्मक विकल्प चुना गया है ताकि कानून के उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जैसा भी मामला हो, प्रशासनिक आदेश सिद्धांत के तहत, अदालत यह देखेगी कि विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण ''उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता या हितों पर कानून या प्रशासनिक आदेश के प्रतिकूल प्रभावों के बीच उचित संतुलन बनाए रखें' कि उनका उद्देश्य सेवा

करना था''। हालाँकि, विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकार को विवेक का क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला दी गई है, लेकिन यह निर्णय लेना अदालत का काम है कि चुना गया विकल्प अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन करता है या नहीं। आनुपातिकता का यही अर्थ है।

हालाँकि, इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून में ''सख्त जांच'' या ''आनुपातिकता'' के सिद्धांत का विकास हाल ही में हुआ है। प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण परंपरागत रूप से बुधवारबरी मैदान पर किया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक कार्रवाई को ''सख्त जांच'' के सिद्धांत को लागू करते हुए कई मामलों में अमान्य घोषित कर दिया गया है। इन स्वतंत्रताओं के मामले में, वेडनसबरी सिद्धांत अब लागू नहीं होते हैं। इंग्लैंड में अदालतें सम्मेलन की अनुपस्थिति में आनुपातिकता को स्पष्ट रूप से लागू नहीं कर सकीं, लेकिन उक्त अधिकारों को सामान्य कानून के लिए बुनियादी मानकर अधिकारों की रक्षा करने का उत्साहपूर्वक प्रयास किया और फिर अदालतों ने सख्त जांच परीक्षण लागू किया। स्पाईकैचर मामले में अटॉर्नी जनरल बनाम गार्जियन न्यूजपेपर्स लिमिटेड (नंबर 2), {1990}

1 एसी 109 (पृ. 283-284 पर), लॉर्ड गोफ ने कहा कि कन्वेंशन और सामान्य कानून के बीच कोई असंगतता नहीं थी। डर्बीशायर काउंटी काउंसिल बनाम टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड {1993} एसी 534 में, लॉर्ड कीथ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामान्य कानून का हिस्सा माना। हाल ही में, आर. बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट में, पूर्व पी. सिम्स, {1999} 3 ऑल ईआर 400 (एचएल), एक पत्रकार को साक्षात्कार देने के कैदी के अधिकार को सामान्य कानून का हिस्सा मानते हुए बरकरार रखा गया था। लॉर्ड हॉबहाउस का मानना था कि प्रशासक की नीति अनुपातहीन थी।

प्रशासनिक निर्णयों में अधिक गहन और चिंताजनक न्यायिक जांच की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैः आर.वी. लॉर्ड सैविले एक्स पी में मौलिक मानवाधिकारों पर फिर से जोर दिया गया था। {1999} 4 ऑल ईआर 860 (सीए), पृष्ठ 870,872 पर। इन सभी मामलों में, अंग्रेजी अदालतों ने परीक्षण को ''आनुपातिकता'' के रूप में वर्णित करने के बजाय ''सख्त जांच'' परीक्षण लागू किया। लेकिन, किसी भी स्थिति में, इन अधिकारों के संबंध में ''बुधवार'' नियम लागू होना बंद हो गया है।

हालाँकि, ''सख्त जांच'' या ''आनुपातिकता'' और प्राथमिक समीक्षा के सिद्धांत को आर. बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव में समझाया गया। एक्स पी ब्रिंड, {1991} 1 एसी 696 वह मामला प्रसारण अधिनियम, 1981

के तहत गृह सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों से संबधित है, जिसमें बीबीसी और आईबीए को ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से कुछ मामलों को प्रसारित करने से परहेज करने की आवश्यकता है जो संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रोकथाम से संबंधित कानून के तहत प्रतिबंधित थे। उग्रवाद के निषेध की सीमा प्रत्यक्ष से जुड़ी हुई थी। संगठनों के सदस्यों द्वारा दिया गया वक्तव्य, हालाँकि, उदाहरण के लिए, इसने ऐसे व्यक्तियों द्वारा फिल्म के माध्यम से प्रसारण को नहीं रोका, बशर्ते कि ''वॉयस-ओवर'' खाता हो, जो उन्होंने व्यक्त किया हो। आवेदक का दावा सीधे तौर पर यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन पर आधारित था। भगवान ब्रिज ने देखा कि कन्वेंशन के अधिकार स्पष्ट रूप से अंग्रजी कानून में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य कानून के लिए बुनियादी थी और कन्वेंशन की अनुपस्थिति में भी, अंग्रेजी न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे (देखें पृष्ठ 748)

> "…..चाहे राज्य सचिव, उसके विवेक की शक्तियों के अंतर्गत, उसके पास मौजूद प्रतिबंध को उचित रूप से लगा सकता है जो कि, कोई भी प्रसारण संगठनों पर लगाया गया''

और वह अदालतें

> “इस आधार से शुरू करने का पूरी तरह से हकदार नहीं है कि कोई भी अभिव्यक्ति की के अधिकार पर प्रतिबंध, उचित है किसी महत्वपूर्ण जनहित से कम इसे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

लॉर्ड टेम्पलमैन ने उपरोक्त मामले में यह भी कहा कि अदालतें ऐसा कर सकती हैं इस प्रश्न पर गौर करें कि क्या एक उचित मंत्री तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप उचित था। उन्होंने कहा कि ''कन्वेंशन के संदर्भ मैं ऐसा कोई भी हस्तक्षेप आवश्यक और आनुपातिक दोनो होना चाहिए (उक्त पृ. 750-51)

प्रसिद्ध परिच्छेद में, ब्रिंड मामले में लॉर्ड ब्रिज द्वारा प्रशासनिक कानून में अदालतों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक समीक्षा के सिद्धांत के बीज बोए गए थे {1991}1 एसी 696। जहां कन्वेंशन अधिकार प्रश्न में थे, अदालतें अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थीं प्राथमिक समीक्षा हालांकि, कन्वेंशन के तहत अधिकारों को प्रभवित नहीं करने वाले मामलों में अदालतें केवल वेडनसबरी सिद्धांतों के आधार पर माध्यमिक समीक्षा के

अधिकार का प्रयोग करेंगी। ऐसे मामलों का जिक्र करतें हुए जहाँ मौलिक

स्वतंत्रता का आह्वान नहीं किया गया था और जहां प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था, यह कहा गया था कि अदालतें तब केवल एक माध्यमिक समीक्षा तक ही सीमित थीं जबकि प्राथमिक निर्णय प्रशासक के पास होगा। लॉर्ड ब्रिज ने प्राथमिक और द्वितीयक समीक्षा को इस प्रकार समझायाः

> ''राज्य के सचिव जिसे संसद ने विवेक सौंपा है वह विशेष प्रतिस्पर्धी जनहित में लगाये गये विशेष प्रतिबंध को उचित ठहरा रहा है। लेकिन, हम यह पूछकर एक द्वितीयक निर्णय लेने के हकदार हैं कि क्या एक उचित राज्य सचिव, उसके सामने मौजूद सामग्री पर, उचित रूप से प्राथमिक निर्णय ले सकता है।''

लेकिन जहां एक प्रशासनिक कार्रवाई को रोयप्पा (1974) 4 एससीसी 3 के आधार पर अनुच्छेद 14 के तहत'' ''
जाती है (जैसे कि उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक मामलों में दंड को चुनौती दी जाती है), सवाल यह होगा कि क्या प्रशासनिक आदेश ''तर्कसंगत'' या ''उचित'' है और परीक्षण वेडनसबरी परीक्षण है। तब अदालतें केवल एक माध्यमिक भूमिका तक ही सीमित रहेंगी और उन्हें

केवल यह देखना होगा कि क्या प्रशासक ने अपनी प्राथमिक भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या उसने अवैध रूप से कार्य किया है या प्रासंगिक तथ्यों को विचार से हटा दिया है या अप्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा है या क्या उसकी दृष्टिकोण वह है जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं अपना सकता। यदि उसकी कार्यवाही इन नियमों को पूरा नहीं करती है, तो इसे मनमाना माना जाएगा। जी.बी. महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद में, {1991} 3 एससीसी 91 पृष्ठ पर। 111 वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने बताया कि प्रशासनिक कानून के संदर्भ में अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासक की ''तर्कसंगतता को वेडनसबरी नियमों के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, {1994} 6 एससीसी 651 पृष्ठ 679-80 पर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,{1985} 1 एससीसी 641 पृष्ठ पर। 691, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ, {1989} 4 एससीसी 187 पृष्ठ पर। 241 एवं उ.प्र. वित्तीय निगम, वी.. जेम कैप (इंडिया)(पी) लिमिटेड, {1993}2 एससीसी 299 एट पी। 307 यह निर्णय करते समय कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई अनुच्छेद 14 के तहत ''मनमाना'' है (अर्थात् अन्यथा भेदभावपूर्ण होने के कारण), इस न्यायालय ने स्वयं को हमेशा बुधवारबरी समीक्षा तक ही सीमित रखा है।

अनुच्छेद 14 के संबंध में अंतिम पूर्ववर्ती पैराग्राफ में बताए गए

सिद्धांतों को अब यहां लागू किया जाना है जहां अनुच्छेद 14 के तहत सज़ा के आदेश की "मनमानी" का सवाल उठाया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांतों और निर्णयित मामलों से, यह होना ही चाहिए। यह माना गया कि जहां दंड से संबंधित एक प्रशासनिक निर्णय है अनुशासनात्मक मामलों में अनुच्छेद 14 के तहत" "
किया जाता है, अदालत एक माध्यमिक समीक्षा प्राधिकारी के रूप में वेडनसबरी सिद्धांतों तक ही सीमित है। अदालत प्राथमिक समीक्षा अदालत के रूप में आनुपातिक लागू नहीं करेगी क्योंकि ऐसे संदर्भ में मौलिक स्वतंत्रता या अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव का कोई मुद्दा लागू नहीं होता है। सज़ा की समीक्षा करते समय अदालत और यदि वह संतुष्ट है कि वेडनसबरी सिद्धांतों का उल्लघंन किया गया है, तो वह उसे आम तौर पर सज़ा की मात्रा के बारे में नए निर्णय के लिए मामले को प्रशासक के पास भेज देना चाहिए। केवल दुर्लभ मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय और अदालतों में लगने वाले समय में लंबी देरी हुई है, और ऐसे चरम या दुर्लभ मामलो में अदालत सज़ा के बारे में अपना दृष्टिकोण रख सकती है।"

बी.सी. में चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य {1995} 6 एससीसी 749 आईटी अवधारित किया गयाः

"उपरोक्त कानूनी स्थिति की समीक्षा यह स्थापित करेगी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, और अपील पर अपीलीय प्राधिकारी तथ्य खोज प्राधिकारी होने के नाते अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से साक्ष्य पर विचार करने की विशेष शक्ति रखते हैं। उनके पास दुराचार की भयावहता या गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित दंड लगाने की शक्ति है। उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, सामान्य रूप से दंड पर अपने निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और कोई अन्य जुर्माना नहीं लगा सकता है। यदि अनुशासनात्मक द्वारा लगाया गया दंड प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोर देता है, यह उचित रूप से राहत को बदलेगा, या तो अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी को लगाए गए जुर्माने पर पुनर्विचार करने का निर्देश देगा, या मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए, यह स्वयं ही हो सकता है। असाधारण और दुर्लभ मामलों में, उसके समर्थन में ठोस कारणों के साथ उचित दंड लगाया जा सकता है।"

भारत संघ और अन्य बनाम जी. गुनयुथम, {1997} 7 एससीसी 463 में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 31 और 32 में आनुपातिकता से संबंधित स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार हैः

"प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता की वर्तमान स्थिति इंग्लैंड और भारत में संक्षेप इस प्रकार किया जा सकता हैः

(1) किसी भी प्रशासनिक आदेश या वैधानिक विवेक की वैधता का आकलन करने के लिए, आम तौर पर वेडनसबरी परीक्षण को यह पता लगाने के लिए लागू किया जाता है कि उनके सामने और कानून के दायरे में जो सामग्री आ गई है उसके आधार पर क्या निर्णय अवैध था या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से ग्रस्त था या ऐसा था जिसे कोई भी समझदार निर्णयकर्ता नहीं कर सकता था। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या प्रासंगिक मामलों को ध्यान में नहीं रखा गया था या क्या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखा गया था या क्या कार्रवाई

प्रामाणिक नहीं थी। अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या निर्णय बेतुका या विकृत था। हालाँकि, अदालत प्रशासक द्वारा उसके लिए खुले विभिन्न विकल्पों में से चुने गए विकल्प की सत्यता पर विचार नहीं करेगी। न ही न्यायालय अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय से प्रतिस्थापित कर सकता है। यह वेडनसबरी (1948) 1 केबी 223 परीक्षण है।

(2) अदालत प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि वह अवैध न हो या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो या इस अर्थ में अतार्किक न हो कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अपमानजनक अवहेलना हो। भविष्य में अंग्रेजी प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता सहित अन्य परीक्षण लाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया गया है। ये सीसीएसयू {1985} एसी 374 सिद्धांत हैं।

(3)(ए) बगडेके के अनुसार {1987}एसी 514, ब्रिंड {1991} में एसी 696 और स्मिथ {1996} 1 सभी ईआर 25 जब तक कन्वेंशन को अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी में शामिल नहीं किया गया है अदालतें केवल यह पता लगाने के लिए द्वितीयक निर्णय का प्रयोग करती है कि क्या निर्णय-निर्माता, उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर, कर सकता था-जिस तरीके से उन्होंने प्राथमिक निर्णय लिया है, उस पर नाराजगी व्यक्त की है।

(3)(बी) यदि आनुपातिकता के सिद्धांत को उपलब्ध कराते हुए कन्वेंशन को इंग्लैंड में शामिल किया गया है, तो अंग्रेजी अदालतें प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता पर प्राथमिक निर्णय देंगी और पता लगाएंगी कि क्या प्रतिबंध असंगत या अत्यधिक है या पर आधारित नहीं है मौलिक स्वतंत्रता और उस पर प्रतिबंध की आवश्यकता का उचित संतुलन।

(4)(ए) हमारे देश में प्रशासनिक स्थिति कानून, जहां उपरोक्त कोई मौलिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, यह है कि अदालतें/न्यायाधिकरण केवल एक माध्यमिक भूमिका निभाएंगे जबकि तर्कसंगतता के बारे में प्राथमिक निर्णय कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी के पास रहेगा। अदालत का द्वितीयक निर्णय क्रमशः लॉर्ड ग्रीन और लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा बताए गए वेडनसबरी और सीसीएसयू सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में अपने निर्णय पर उचित रूप से पहुंचे है।

(4)(बी) चाहे प्रशासनिक या कार्यकारी के मामले में। मौलिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कार्रवाई में, हमारे देश में अदालतें ''आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करेंगी और एक प्राथमिक भूमिका मानेंगी, जिसे उचित मामले में तय करने के लिए खुला रखा जाएगा, जहां इस तरह की कार्रवाई से मौलिक स्वतंत्रता का अपमान करने का आरोप

लगाया जाता है। तब यह तय करना आवश्यक होगा कि क्या अदालतों की प्राथमिक भूमिका केवल तभी होगी जब अनुच्छेद 19,21 आदि के तहत स्वतंत्रताएं शामिल होंगी न कि अनुच्छेद 14 के लिए।

अंत में, हम वर्तमान मामले पर आते हैं। हमारे सामने यह तर्क नहीं रखा गया है कि कोई मौलिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। इसलिए हमें ''आनुपातिकता'' के प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं हैं। यहां ऐसा कोई तर्क नहीं है कि दी गई सज़ा अवैध है या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से दूषित है। जहां तक'' '' , ट्रिब्यूनल ने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि यह निर्णय ऐसा है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने पक्ष और विपक्ष का आकलन किया हो, उस पर नहीं पहुंच सकता था और न ही सामग्री के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष है कि अवज्ञा कर सजा दी गई है। ''अपमानजनक'' तर्क की अवज्ञा। न तो वेडनसबरी और न ही सीसीएयू परीक्षण संतुष्ट हैं। हमें अभी भी ''रंजीत ठाकुर {1987} 4 एससीसी 611'' की व्याख्या करनी है। इन सभी निर्णयों में जो सामान्य सूत्र चल रहा है वह यह है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अतार्किक न हो या

प्रक्रियात्मक अनुपयुक्तता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा झकझोंर करता हो या नैतिक मानकों के विरूद्ध वेडनसबरी के मामले (सुप्रा) में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर न्यायालय प्रशासक द्वारा किए गए विकल्प की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा और न्यायालय को प्रशासक के फैसले के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक ही सीमित है, न कि निर्णय तक।

दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगया गया दंड जब तक न्यायालय/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोर न दें, तब तक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा मुकदमों को छोटा करने के लिए, असाधारण और दुर्लभ मामलों में, इसके समर्थन में ठोस कारण दर्ज करके उचित दंड लगाया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया में यदि लगाया गया दंड आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को लगाए गए दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना उचित होगा।

मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय ने कोई कारण दर्ज नहीं किया कि कैसे और क्यों उसने सज़ा को आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन पाया। वहां भी इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं हैं।

एक बैंक अधिकारी को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करना आवश्यक है। वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के पैसे का लेनदेन करता है। बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम और ऐसा कुछ भी न करना जो एक बैंक अधिकरी के लिए अनुचित हो। अच्छा आचरण और अनुशासन बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कामकाज से अविभाज्य है। जैसा कि इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम निकुंज बिहारी पटनायक, {1996} 9 एससीसी 69 में देखा था, यह कहने के लिए कोई बचाव उपलब्ध नहीं है कि मामले में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, जब अधिकारी /कर्मचारी ने बिना अधिकार के कार्य किया। किसी संगठन, विशेष रूप से बैंक, का अनुशासन उसके प्रत्येक अधिकारी और अधिकारी जो अपने आवंटित क्षेत्र के भीतर कार्य करते है और संचालन करते है पर निर्भर करता है।अपने अधिकार से परे कार्य करना अपने आप में अनुशासन का उल्लंघन है और कदाचार है। कर्मचारी के खिलाफ आरोप आकस्मिक प्रकृति के नहीं थे और गंभीर थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है।

इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब किसी न्यायालय को लगता है कि सज़ा आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है, तो

उसे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों को दर्ज करना होगा। मात्र यह अभिव्यक्ति कि सज़ा आश्चर्यजनक रूप से असंगत है, कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन,{1971} आई ऑल ई.आर. 1148 में लॉर्ड डेनिंग एम.आर. ने कहा, ''कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है''। अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) ढक्कन में। वी. क्रैबट्री, {1974} एलसीआर 120 में यह देखा गयाः '' कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है''। कारण विवाद के निष्कर्ष पर पहुंचना निर्णय लेने वाले के दिमाग के बीच जीवित सेतु है''।

निर्णय के कारण वस्तुनिष्ठता द्वारा व्यक्तिपरकता को प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर इसलिए दिया जाता है कि यदि निर्णय ''स्फिंक्स के गूढ चेहरे'' को प्रकट करता है, तो न्यायालय की चुप्पी के लिए अपना अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना देती है। कारण वर्णित करने का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक और तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष जान सकता है। जानें कि फैसला उसके खिलाफ क्यों गया। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना।''   ''

साथ असंगत है न्यायिक प्रदर्शन-

इन पहलुओं को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और अन्य बनाम पी.सी. मामले में उजागर किया गया था। कक्क्ड़ {2003} 4 एससीसी 364।

मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय का फैसला किंतु-परंतु से भरा है। कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि सज़ा किसी त्रुटि से पीड़ित हैै सज़ा की मात्रा पर दोबारा विचार करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी नेकनीयती साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। हालाँकि उन्होंने यह रूख अपनाया कि उन्होंने मुख्य कार्यालय को रुपये निकालने के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए भी अधिकारी के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि निकासी 06.05.1992 को हुई थी, न कि 09.05.1992 को, जैसा कि दावा किया गया था। प्रत्यर्थी कर्मचारी ने 20,000 रुपये भारतीय स्टैट बैंक के खाते से 06.05.1992 को निकाले और दोबारा 5,000 रुपये नकद में से निकाले।

उपरोक्त स्थिति होने के कारण उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसे निरस्त कर दिया जाता है। प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है।

अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

वी.एस.एस.

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती शिल्पा समीर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।